आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 11.10.2025 **समय : 0705**

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन–धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे।
- सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में "सर्किल रेट" के निर्धारण एवं अनुप्रयोग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा औरं सुधार का अनुरोध किया है।
- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ओग्राब्राज में सरकारी योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया।
- शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कल द्वीप समूह के 35 F4S केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "स्कूल के लिए फुटबॉल" पहल की शुरुआत की।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन–धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसानों से भी बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित दर्शाता है। द्वीपसमूह में भी इस कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के तहत तेरह अक्टूबर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक श्रम आयुक्त कार्यालय के सभागार में शाम तीन बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में श्रम और रोज़गार मंत्रालय, सामाजिक सुरक्षा के उप सचिव शिवकान्त कुमार शामिल होंगे।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट–

<><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने प्रशासन से द्वीपसमूह में "सर्किल रेट" के निर्धारण एवं अनुप्रयोग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा औरं सुधार का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में, कहा कि "सर्किल रेट" तय करने की वर्तमान पद्धति का भारतीय स्टाम्प अधिनियम या पंजीकरण अधिनियम के तहत कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, भूमि पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों पर लागू होता है, और अंडमान निकोबार प्रशासन ने ऐसी दरों के निर्धारण हेतु प्रावधानों या नियमों को नहीं अपनाया है। सांसद ने आगे कहा कि भूमि की दरें कानूनी रूप से तय करने का अधिकार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 की धारा 45 के अंतर्गत निहित है। श्री रे ने संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए तत्काल सुधार का आह्वान किया।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, ने कल ग्राम पंचायत कन्यापुरम का दौरा कर ग्रामीण विकास पहलों की समीक्षा और आंकलन किया। दौरे के दौरान, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवनिर्मित सीसी सड़क और उचित जल निकासी सुविधाओं के साथ सड़क के नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया। इसके अलावा, कन्यापुरम में एक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए भूमि निर्धारित की गई। जिला उपायुक्त ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देने के लिए ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

<><><><><><><>

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कल 'ए.आई. अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन का खाका' शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य भारत को ए.आई.–संचालित कार्य के उभरते भविष्य के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत की ताकत उसके लोगों में निहित है। उन्होंने कहा कि सही दृष्टिकोण और समन्वय के साथ, भारत दुनिया की ए.आई. कार्यबल राजधानी बन सकता है। यह रिपोर्ट 2031 तक संभावित रोज़गार विस्थापन की चेतावनी तो देती ही है, साथ ही एक बड़े अवसर की भी पहचान करती है, जो एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में 40 लाख तक नई ए.आई.–सक्षम नौकरियों का सृजन है।

<><><><><><><>

नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्यौहारों के दौरान हवाई किराये को किफायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी।

इस अवसर पर श्री नायडू ने विमानन कंपनियों द्वारा यात्रियों के लिए चलाए गए शिकायत निवारण अभियान की भी समीक्षा की और एयरलाइन्स को इस संबंध में समय पर शिकायतों के निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराये पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में ओग्राब्राज सामुदायिक भवन में एक सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करना था। शिविर के दौरान, कुल 76 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। ग्रामीण विकास, नागरिक आपूर्ति और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान सत्यापित की गई, ताकि उन्हें संबंधित कल्याणकारी योजनाओं में आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों, लाभों और योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत प्रधान, खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता–विद्युत, कनिष्ठ अभियंता, तहसीलदार के साथ लाभार्थी और ग्रामीण उपस्थित थे।

<><><><><><><>

शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कल द्वीप समूह के 35 F4S केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "स्कूल के लिए फुटबॉल" पहल की शुरुआत की। नारा है– फोन नहीं फुटबॉल। खेलों को बढ़ावा देने और बच्चों में मोबाइल की लत को कम करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 8 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फुटबॉल कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि F4S पहल न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देगी, बल्कि छोटे बच्चों में नशे की बढ़ती लत को रोकने में भी मदद करेगी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीरंदाजी संघ ने दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिला के लिए जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रही है। यह चैम्पियनशिप 25 और 26 अक्टूबर को श्री विजयपुरम मायाबंदर में आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय चैम्पियनशिप के बाद ओपन स्टेट तीरंदाजी चैंपियनशिप 8 और 9 नवंबर श्री विजयपुरम में आयोजित की जाएगी। इच्छुक तीरंदाजों से 22 अक्टूबर और 5 नवंबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा करने को कहा गया है।

<><><><><><><>